

भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. † *185
दिनांक 12.03.2025 को उत्तर देने के लिए

परियोजना निगरानी इकाई द्वारा खदानों का संचालन

†*185. श्री बिप्लब कुमार देबः

श्री कृपानाथ मल्लाहः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नीलाम की गई 500 खनिज और कोयला खदानों का राज्यवार व्यौरा क्या है और इन खनिज और कोयला खदानों के संचालन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा नव-स्थापित परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) के माध्यम से क्या विशिष्ट उपाय लागू किए गए हैं;

(ख) पीएमयू विभिन्न मंत्रालयों और राज्य प्राधिकरणों के बीच समन्वय किस प्रकार बढ़ाएगा ताकि खदानों का संचालन तेजी से हो सके; और

(ग) खनन कार्यों के लिए आवश्यक सांविधिक मंजूरी के अनुपालन की निगरानी में पीएमयू की क्या भूमिका है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): विवरण सदन के पठल पर रख दिया गया है।

'परियोजना निगरानी इकाई द्वारा खदानों का संचालन' के संबंध में दिनांक 12 मार्च, 2025 को उत्तर देने हेतु श्री बिप्लब कुमार देब और श्री कृपानाथ मल्लाह, सांसदों द्वारा लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. 185 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) : अब तक विभिन्न राज्यों में 457 गैर कोयला खनिज ब्लॉकों और 131 कोयला ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। ब्लॉकों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-। में दिया गया है।

परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना प्रमुख सांविधिक मंजूरियों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाकर नीलाम किए गए ब्लॉकों के संचालन में तेजी लाने के लिए की गई है। पीएमयू मंजूरियों को सरल बनाने और समयबद्ध तरीके से मंजूरियां और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, राज्य प्राधिकरणों और नीलाम किए गए ब्लॉकों के अधिमानित बोलीदाताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इसके अलावा, पीएमयू लंबित अनुमोदनों का रिकार्ड रखकर विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करता है, मौजूदा पद्धति के तहत अनुमोदन प्राप्त करने में बोलीदाताओं के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं की पहचान करता है तथा अनुमोदन प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करता है।

अनुलग्नक-I

'परियोजना निगरानी इकाई द्वारा खदानों का संचालन' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 185 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्य-वार नीलामी सारांश (गैर-कोयला ब्लॉक)

क्र. सं.	राज्य	राज्य सरकार द्वारा नीलाम किए गए खनिज ब्लॉक	केन्द्र सरकार द्वारा नीलाम किए गए महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक	नीलाम किए गए कुल खनिज ब्लॉक
1	आंध्र प्रदेश	25	1	26
2	अरुणाचल प्रदेश	-	4	4
3	असम	3	-	3
4	बिहार	1	3	4
5	छत्तीसगढ़	37	1	38
6	गुजरात	25	-	25
7	गोवा	12	-	12
8	झारखण्ड	10	1	11
9	कर्नाटक	45	2	47
10	मध्य प्रदेश	90	3	93
11	महाराष्ट्र	40	1	41
12	ओडिशा	48	3	51
13	राजस्थान	88	-	88
14	तमिलनाडु	-	2	2
15	तेलंगाना	2	-	2
16	उत्तर प्रदेश	7	3	10
कुल योग		433	24	457

राज्य-वार सारांश (कोयला ब्लॉक)

क्र. सं.	राज्य	नीलाम किए गए कुल कोयला ब्लॉक
1	अरुणाचल प्रदेश	1
2	असम	2

3	छत्तीसगढ़	19
4	झारखण्ड	34
5	मध्य प्रदेश	31
6	महाराष्ट्र	13
7	ओडिशा	25
8	पश्चिम बंगाल	6
	कुल योग	131